Social Justice Union

दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, मंगलवार 27 अप्रैल 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 206

देश में अब तक 14 करोड़ 19 लाख से अधिक को कोविड टीका लगा, भारत में कोविड टीकाकरण के 100 दिन पूरे

नईदिल्ली (आरएनएस)। विश्व में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत भारत में कोविड-19 टीके की दी जा चुकी खुराक की कुल संख्या आज 14.19 करोड़ से अधिक हो गई है। साथ ही टीकाकरण अभियान ने कल 100 दिन पूरे कर लिए।

रिपोर्ट के अनुसार 20,44,954 सत्रों के जरिए कोविड वैक्सीन की कुल 14,19,11,223 खुराक दी जा चुकी हैं। टीकाकरण लाभार्थियों की कुल संख्या में वे 92,98,092 एचसीडब्ल्यू शामिल हैं, जिन्होंने वैक्सीन की पहली खुराक ली है और 60,08,236 ऐसे एचसीडब्ल्यू भी शामिल हैं, जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी खुराक ले ली है। इसके अलावा पहली खुराक लेने वाले 1,19,87,192 एफएलडब्ल्यू, दूसरी खुराक लेने वाले 63,10,273 एफएलडब्ल्यू, इसके साथ-साथ 60 साल से अधिक आयु के पहली खुराक लेने वाले 4,98,72,209 और दूसरी खुराक लेने वाले 79,23,295 लाभार्थियों के साथ-साथ 4,81,08,293 पहली खुराक लेने वाले और 24,03,633 दूसरी खुराक लेने वाले 45 से 60 वर्ष की आयु के लाभार्थी भी शामिल हैं।

देश में अभी तक दी गई कुल खुराक में आठ राज्यों का 58.78 प्रतिशत योगदान है।

पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की करीब 10 लाख खुराक दी गई।

टीकाकरण अभियान के 100वें दिन (25 अप्रैल, 2021) कोविड-19 के 9,95,288 टीके की खुराक दी गई। इसमें से 6,85,944 लाभार्थियों को 11,984 सत्रों के जरिए पहली खुराक तथा 3,09,344 लाभार्थियों को टीके की दूसरी खुराक दी गई।

भारत में आज तक कुल मिलाकर 1,43,04,382 कोविड मरीज ठीक हुए हैं। राष्ट्रीय रिकवरी दर 82.62प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,19,272 कोविड मरीज ठीक हुए है। बीमारी से उबरने वाले मरीजों की संख्या में 10 राज्यों का योगदान 78.98 प्रतिशत है।

पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 3,52,991 नये मामले दर्ज किए गए।

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान सहित 10 राज्यों में नये संक्रमण के 74.5 प्रतिशत मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

महाराष्ट्र में सबसे अधिक 66,191 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद 35,311 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जबकि कर्नाटक में 34,804 नए मामले सामने आए हैं।

12 राज्यों में, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, दैनिक नए मामलों में बढ़ोतरी का रूझान जारी है।

भारत में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 28,13,658 हो गई है। यह संख्या देश के कुल संक्रमित मामलों का 16.25 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल सक्रिय मामलों की संख्या में 1,30,907 मामलों की बढ़ोतरी हुई है।

भारत के कुल सक्रिय मामलों में आठ राज्यों- महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और केरल का कुल मिलाकर 69.67 प्रतिशत योगदान है।

कोविड से जुड़ी राष्ट्रीय मृत्यु दर गिर रही है और इस समय 1.13 प्रतिशत है।

पिछले 24 घंटों के दौरान 2,812 कोविड मरीजों की मौत हुई है। 10 राज्यों का मौत के नए मामलों में 79.66 प्रतिशत योगदान है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 832 लोगों की जान गई, इसके बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा 350 लोगों की मौत हुई।

पिछले 24 घंटे के दौरान पांच राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड से किसी रोगी की मौत नहीं हुई है। इन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम हैं- दमन दीव और दादर नगर हवेली, त्रिपुरा, लक्षदीप, मिजोरम और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह।

महत्वपूर्ण एवं खास

कोविड वैक्सीन के लिए कच्चा माल देगा अमेरिका

नईदिल्ली (आरएनएस)। अमेरिका ने कोरोना से जंग में भारत को मदद का हाथ बढ़ाते हुए कहा है कि वह कोविड-19 वैक्सीन के लिए शीघ्र कच्चा माल और मेडिकल उपकरण मुहैया करायेगा। एक बयान में रविवार को कहा गया कि अमेरिका ने कोविल्ड वैक्सीन के भारतीय निर्माण के लिए तत्काल आवश्यक कच्चे माल के स्रोतों की पहचान की है जो तुरंत भारत के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

मोदी की जापानी पीएम सुगा से कोविड-19 पर हुई चर्चा

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने जापानी समकक्ष योशिहिदे सुगासे फोन पर बात कर दोनों देशों के बीच जारी विभिन्न द्विपक्षीय पहलों की प्रगति की समीक्षा की और कोविड-19 सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से फोन पर बात हुई। हमने दोनों देशों के बीच जारी विभिन्न द्विपक्षीय पहलों की समीक्षा की। हमने उच्च प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और कोविड-19 महामारी से साथ मिलकर मुकाबला करने सहित आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच यह चर्चा ऐसे समय में हुई है जब भारत में कोविड-19 तेजी से अपने पांव पसार रहा है।

रेलवे ने अब तक विभिन्न राज्यों में 302 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की

नईदिल्ली (आरएनएस)। कुछ दिन पूर्व ही मुंबई से विशाखापत्तनम के लिए खाली टैंकर लेकर ऑक्सीजन लेने पहली रेलगाड़ी निकली थी। तब से अब तक भारतीय रेलवे ने देश के विभिन्न राज्यों में 302 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सुरक्षित आपूर्ति की है। इसके अलावा 154 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस अलग-अलग गंतव्य की ओर बढ़ रही हैं। भारतीय रेलवे ने जीवन रक्षक ऑक्सीजन की सभी इच्छुक राज्यों में आपूर्ति की चुनौती स्वीकार की है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से ऑक्सीजन के चार टैंकर लेकर रवाना हुई एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस के आज दिल्ली पहुंचने की संभावना है। महाराष्ट्र के लोगों के लिए गुजरात के राजकोट, हापा से 3 टैंकरों में 44 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर निकली रेलगाड़ी आज मुंबई के नजदीक कलंबोली पहुंच गई। एक अन्य रेलगाड़ी पांच टैंकरों में 90 मीट्रिक टन ऑक्सीजन (5 टैंकरों में) लेकर झारखंड के बोकारो से उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी है। इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस के कल तड़के लखनऊ पहुंचने की संभावना है। लखनऊ से एक अन्य ऑक्सीजन एक्सप्रेस अतिरिक्त ऑक्सीजन लेने के लिए बोकारो के लिए जल्द ही रवाना होगी। भारतीय रेलवे सभी राज्य सरकारों से ऑक्सीजन ढुलाई के लिए मिलने वाले अनुरोध पर सक्रियता से कदम उठा रहा है और अतिरिक्त ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है।

कोरोना संकट... आस्ट्रेलियाई क्रिकेटर कमिंस ने दान दिये 50 हजार डॉलर

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोलकाता नाइट राइडर्स के आस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने सोमवार को भारत में कोविड-19 मामलों से भरे अस्पतालों में आक्सीजन की आपूर्ति के लिये 'पीएम केयर्स फंड' में 50 हजार डॉलर दान देने की घोषणा की।

कमिंस ने साथ ही कहा कि उन्हें सलाह दी गयी है कि भारत सरकार इंडियन प्रीमियर लीग जारी रखने का समर्थन करती है और मानती है इस मुश्किल समय में यह 'कुछ घंटे का आनंद' मुहैया कराती है। अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बयान में उन्होंने यह घोषणा की और अन्य शीर्ष खिलाड़ियों से भी ऐसा करने का अनुरोध किया क्योंकि देश कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि यहां इस पर काफी चर्चा हो रही है कि क्या इंडियन प्रीमियर लीग का जारी रहना उचित है जबकि कोविड-19 संक्रमण की दर काफी ज्यादा बनी हुई है। कमिंस ने इस बयान में कहा कि मुझे सलाह दी गयी है कि भारत सरकार समझती है कि इंडियन प्रीमियर लीग खेलने से लॉकडाउन में रह रहे लोगों को प्रत्येक दिन कुछ घंटे का आनंद और राहत मिलती है जबकि देश मुश्किल समय से गुजर रहा है।

कोरोना के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे सेना के रिटायर्ड डॉक्टर्स

» पीएम मोदी ने सीडीएस बिपिन रावत के साथ की बैठक

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में निरंतर तेज हो रही दूसरी कोरोना लहर के बीच देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम के साथ उन्होंने महामारी से निपटने के लिए सेना की तैयारियों और शुरू किए गए कार्यों की समीक्षा की।

मुलाकात के बाद पीएमओ ने यह जानकारी दी। पीएमओ के अनुसार सीडीएस रावत ने पीएम मोदी को बताया कि बीते एक-दो साल में सेना से समय पूर्व रिटायरमेंट लेने वाले चिकित्सा अधिकारियों को भी उनके मौजूदा निवास के आसपास के कोविड सेंटर में सेवाएं देने के लिए तलब किया जा रहा है। पीएमओ के अनुसार सेना के अन्य रिटायर चिकित्सा अधिकारियों से भी आग्रह किया गया है कि वे इमर्जेंसी हेल्पलाइन के जरिए परामर्श सेवाएं देने के लिए उपलब्ध रहें। जनरल रावत ने पीएम मोदी को यह भी बताया कि सेना के कमान मुख्यालयों के सारे चिकित्सा अधिकारियों के अलावा कोर मुख्यालयों, डिवीजन मुख्यालयों व वायुसेना व नौसेना के ऐसे ही मुख्यालयों के सभी मेडिकल ऑफीसरों को भी अस्पतालों में तैनात कर दिया गया है। सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक कमांड, कोर, डिविजन और नौसेना तथा वायुसेना के समान मुख्यालयों में तैनात सभी मेडिकल अफसर अस्पतालों में तैनात किए जाएंगे। अस्पतालों में डॉक्टरों की मदद के लिए बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ को तैनात किया जा रहा है। सशस्त्र बलों के विभिन्न प्रतिष्ठानों के पास उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों को दिए जाएंगे।

सेना की मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होंगी

बयान के मुताबिक सशस्त्र बल बड़ी संख्या में मेडिकल प्रतिष्ठान तैयार कर रहे हैं, जहां भी संभव होगा, सेना की मेडिकल सुविधाएं आम लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी। रावत के साथ बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने देश-विदेश से ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक सामग्री की भारतीय वायुसेना द्वारा परिवहन की तैयारियों की समीक्षा भी की।

भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम शुरू किया

सांसद जमैया त्सेरिंग नामग्याल, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के माननीय एलजी के सलाहकार, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के एलजी के सचिव और लेह के चीफ एक्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी ग्यालसन, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के मुख्य सचिव उपस्थित थे।

नईदिल्ली (आरएनएस)। लद्दाख के युवाओं के बेहतर भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भारतीय सेना की सतत पहल के हिस्से के रूप में, लेह स्थित कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी ने कॉरपोरेट पार्टनर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और कार्यकारी एजेंसी राष्ट्रीय अखंडता एवं शैक्षणिक विकास संघटन (एनआईईडीओ) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लेह में 26 अप्रैल को हुए इस समझौते के अवसर पर जीओसी 14 कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन, एचपीसीएल के क्षेत्रीय प्रबंधक, रिटेल जम्मू एवं कश्मीर प्रिंस सिंह, एनआईईडीओ के मैनेजिंग ट्रस्टी और सीईओ डॉ. रोहित श्रीवास्तव, सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। समारोह में लेह के

प्रोजेक्ट लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स : एक उत्कृष्टता और देखभाल के केंद्र की परिकल्पना संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के युवाओं के लिए बेहतर भविष्य को सुरक्षित करने के लिए की गई है। जो कि प्रवेश परीक्षाओं के लिए 12 महीने की अवधि का मार्गदर्शन और उसके लिए एक पूर्णकालिक आवासीय कार्यक्रम है। जिसके जरिए लद्दाख के युवाओं को देश में मौजूद विभिन्न मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज प्रवेश दिलाया जा सके। भारतीय सेना के तत्वावधान में कार्यक्रम को कानपुर स्थित एनजीओ, राष्ट्रीय अखंडता और शैक्षणिक विकास संगठन (एनआईईडीओ) द्वारा निष्पादित किया जाएगा। भारतीय सेना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के जरिए जरूरी आर्थिक सहायता के साथ प्रशासन और रसद के परिचालन की देखरेख करेगी।

कानपुर स्थित शैक्षणिक ट्रस्ट जिसे राष्ट्रीय अखंडता और शैक्षणिक विकास संगठन (एनआईईडीओ) नाम दिया गया है। उसे कार्यक्रम को निष्पादित करने की जिम्मेदारी दी गई है। जो न केवल बच्चों का मार्गदर्शन करेगा बल्कि उनकी भविष्य की योजनाओं में भी सहायता करेगा। साथ ही उन्हें मूल्यों आधारित शिक्षा भी प्रदान करेगा। इसके तहत प्राथमिक कैरियर चुनने, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, महत्वपूर्ण जीवन दक्षताओं, नेतृत्व क्षमता, व्यक्तिगत विकास, देखभाल कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यक्तित्व विकास के साथ उन्हें उस वक्त तक तैयार किया जाएगा जब तक वह राष्ट्र के लिए उत्पादक मानव संसाधन नहीं बन जाते।

3 टैंकर के साथ पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई पहुंची

नईदिल्ली (आरएनएस)। तरल (लिक्विड) मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) से भरे तीन टैंकरों के साथ रो-रो सेवा संडे को 18.03 बजे गुजरात के हापा से रवाना हुई और सोमवार को महाराष्ट्र के कलंबोली पहुंची। ऑक्सीजन एक्सप्रेस की अबाध और तेज आवाजाही के लिए उसे ग्रीन कॉरीडोर मुहैया कराया गया। रेल मंत्रालय द्वारा संचालित ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों के माध्यम से देश भर में कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है।

ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 860 किलोमीटर की दूरी तय की है। ये टैंकर लगभग 44 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर पहुंचे है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस की सुचारू आवाजाही के लिए कलंबोली गुड्स शेड में आवश्यक व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस सभी सुरक्षा मापदंडों को ध्यान में रखते हुए हापा से वीरमगाम, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वसई रोड और भिवंडी रोड से कलंबोली पहुंची है। इन ऑक्सीजन टैंकरों की आपूर्ति मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज, जामनगर द्वारा की गई है।

रेलवे ने अब तक मुंबई नागपुर-नासिक होते हुए विजाग तक और लखनऊ से बोकारो और उसकी वापसी के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई है। और लगभग 150 टन लिक्विड ऑक्सीजन 25.4.2021 तक पहुंचाई गई है।

संक्रमण के बावजूद चुनावी रैलियों पर रोक नहीं 'अधिकारियों पर दर्ज हो हत्या का मुकदमा'

» मद्रास हाईकोर्ट की चुनाव आयोग को फटकार

चेन्नई (आरएनएस)। कोरोना काल में बढ़ रहे मामलों पर मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि यह जानते हुए भी कि कोरोना संक्रमण अभी है बावजूद चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगाई। इसके लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मामला चलाया जाना चाहिए। साथ ही आयोग से कहा कि 2 मई को तैयारियां पहले से बता दें वरना मतगणना रोक दी जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी ने चुनाव आयोग से कहा, आपकी संस्था कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। मद्रास हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर 2 मई को आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित योजना नहीं बनाई तो मतगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाएगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने ईसी से कहा, लोगों का स्वास्थ्य सबसे अहम है और यह चिंताजनक है कि संवैधानिक अधिकारियों को ऐसी बातें याद दिलानी पड़ती है। जब कोई शख्स जीवित रहेगा तभी वह अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का लाभ उठा सकेगा। उन्होंने कहा कि, स्थिति अब अस्तित्व और सुरक्षा की है। इसके बाद सब कुछ आता है। अदालत में जब चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि उनकी ओर से कोविड गाइडलाइन्स का पालन किया गया, वोटिंग डे पर नियमों का पालन किया गया था। इसपर अदालत नाराज हुई और पूछा कि जब प्रचार हो रहा था, तब क्या चुनाव आयोग दूसरे प्लेनेट पर था। सुनवाई के दौरान राज्य के स्वास्थ्य सचिव के परामर्श के बाद, हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि मतगणना के दिन कोरोना प्रोटोकॉल लागू करने की योजना को 30 अप्रैल के दिन अदालत के समक्ष पेश किया जाए।

पंजाब के किसानों को पहली बार बैंक खातों में सीधे भुगतान मिलना शुरू

नईदिल्ली (आरएनएस)। पहली बार, पंजाब के किसानों ने अपनी गेहूं की फसल की बिक्री के लिए सीधे अपने बैंक खातों में भुगतान प्राप्त करना शुरू कर दिया है। करीब 8,180 करोड़ रुपये पहले ही सीधे पंजाब के किसानों के खातों में भेज दिए गए हैं।

2021-22 के मौजूदा रबी विपणन सत्र (आरएमएस) में, भारत सरकार ने वर्तमान मूल्य समर्थन योजना के अनुरूप किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर रबी फसल की खरीद जारी रखी है।

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं अन्य खरीद राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में गेहूं की खरीद तेज गति से चल रही है और 25 अप्रैल तक 222.33 एलएमटी

(लाख मीट्रिक टन) से अधिक फसल की खरीद की जा चुकी है जबकि पिछले साल इसी अवधि में 77.57 लाख मीट्रिक टन फसल की खरीद की गयी थी। 25 अप्रैल तक की गयी 222.33 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से, पंजाब - 84.15 लाख मीट्रिक टन (37.8 प्रतिशत), हरियाणा- 71.76 लाख मीट्रिक टन (32.27 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश -51.57 लाख मीट्रिक टन (23.2 प्रतिशत) ने प्रमुख योगदान दिया है।

करीब 21.17 लाख गेहूं के किसानों को पहले से ही 43,912 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य के साथ मौजूदा रबी विपणन सत्र में खरीद अभियानों से लाभान्वित किया जा चुका है।

25 अप्रैल तक पंजाब में लगभग 8,180 करोड़ रुपये और हरियाणा में लगभग 4,668 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में भेजे गए हैं।

इस वर्ष, सार्वजनिक खरीद के इतिहास में तब एक नया अध्याय जुड़ा जब हरियाणा और पंजाब ने एमएसपी के अप्रत्यक्ष भुगतान का तरीका छोड़ते हुए भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी खरीद एजेंसियों द्वारा किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन पैसे भेजने का तरीका अपनाया। इससे पंजाब/ हरियाणा के किसान काफी खुश हैं क्योंकि वन नेशन, वन एमएसपी, वन डीबीटी के तहत, पहली बार उन्हें बिना किसी देरी और कांट-छाट के अपनी फसलों की बिक्री के लिए सीधे लाभ प्राप्त हो रहा है।